



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 10 1995/ आषाढ़ 19, 1917

No. 298]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 10, 1995/ASADHA 19, 1917

विन्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1995

सा.का.नि. 541(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 29 की उप-धारा (2) के खण्ड (घक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अध्याय 6क के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए जांच करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (न्याय-निर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की प्रक्रिया) नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है;

(ख) “न्यायनिर्णायक अधिकारी” से बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 153 के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) “जांच” से धारा 153 में निर्दिष्ट जांच अभिप्रेत है।

3. न्यायनिर्णायक अधिकारी की जांच करने के लिए नियुक्ति :—जब कभी बोर्ड की यह राय हो कि अधिनियम के अध्याय 6क में के उपबंधों में से किसी के अधीन न्यायनिर्णय करने के लिए आधार है, वह अपने किसी अधिकारी को, जो प्रभाग प्रमुख की पंक्ति से नीचे का न हो, उक्त प्रयोजन के लिए जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

4. जांच करना :—(1) धारा 15क, 15ख, 15ग, 15घ, 15ङ, 15च, 15छ, और 15ज के अधीन यह न्याय-निर्णय करने के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति ने धारा 15क, 15ख, 15ग, 15घ, 15ङ, 15च, 15छ और 15ज में से किसी धारा में यथा विनिर्दिष्ट उल्लंघन किया है या नहीं, जांच करने में, न्यायनिर्णायक अधिकारी, प्रथमतः, ऐसे व्यक्ति को सूचना जारी करेगा जिसमें ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए (जो उसकी तामील की तारीख से चौदह दिन से कम न हो), हेतुक दणित करना अपेक्षित हो कि उसके विरुद्ध जांच क्यों न की जाए।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रत्येक सूचना में उस अपराध की, जिसके बारे में उसके द्वारा किया गया अभिकथित है, प्रकृति उपदर्शित होगी।

(3) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी को, ऐसे व्यक्ति द्वारा दणित हेतुक, यदि कोई हो पर विचार करने के पश्चात्, यह गय है कि जांच की जाना चाहिए, तो वह उस व्यक्ति के स्वयं या उसके वकील या अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि की मार्फत उपसंज्ञात होने के लिए कोई तारीख नियत करते हुए सूचना जारी करेगा।

(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी, नियत तारीख को, ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गई है, या उसके वकील या प्राधिकृत प्रतिनिधि को उस अपराध के बारे में, जिसके बारे में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अभिकथित है, अधिनियम, नियमों या विनियमों के उपबंधों को, जिनकी बाबत यह अभिकथित है कि उल्लंघन किया गया है, उपदर्शित करते हुए स्पष्ट करेगा।

(5) उसके पश्चात् न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति को ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य, जिसे वह जांच के लिए सुसंगत समझे, पेश करने का अवसर देगा और यदि आवश्यक हो तो, सुनवाई किसी भविष्यवर्ती तारीख तक स्थगित की जा सकेगी और ऐसा साक्ष्य लेने में न्यायनिर्णायक अधिकारी साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 11) के उपबंधों को पालन करने के लिए आबद्ध नहीं होगा।

परन्तु उपनियम (3) में निर्दिष्ट सूचना और उपनियम (3), उप-नियम (4) और उप-नियम (5) में निर्दिष्ट वैयक्तिक सुनवाई को, संबद्ध व्यक्ति के अनुरोध पर, अभित्य-जित किया जा सकेगा।

(6) न्यायनिर्णायक अधिकारी को इस नियम के अधीन जांच करने के दौरान, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुपरिचित है, साक्ष्य देने के लिए या कोई ऐसा दस्तावेज, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो, पेश करने के लिए समन करने और उसे हाजिर कराने की शक्ति होगी।

(7) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (3) द्वारा यथा अपेक्षित न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपसंज्ञात होने

में असफल रहता है, उपेक्षा करता है या उसमें इन्कार करता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में ऐसा करने के लिए कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् जांच को अग्रसर कर सकेगा।

5. न्यायनिर्णायक अधिकारी का आदेश—(1) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी को, न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य के संबंध में विचार करने पर, यह समाधान हो जाता है कि व्यक्ति धारा 15ख की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट धाराओं में से किसी के अधीन शास्ति के लिए दायी हो गया है, तो वह, लिखित आदेश द्वारा, धारा 15क में विनिर्दिष्ट सुसंगत धारा या धाराओं के उपबंधों के अनुसार ऐसी शास्ति, जो वह ठीक समझे, अधिरोपित कर सकेगा।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी, धारा 15क के अधीन शास्ति की मात्रा का न्यायनिर्णय करने समय, निम्नलिखित बातों पर सम्यक ध्यान देगा, अर्थात् :—

(क) व्यक्ति के परिणामस्वरूप किए गए अनुचित अभिलाभ या अनुचित लाभ की, जहां कहीं अनु-मान्य हो, मात्रा;

(ख) व्यक्ति के परिणामस्वरूप किसी विनिधानकर्ता या विनिधानकर्ताओं के समूह को कारित हानि की मात्रा;

(ग) व्यक्ति की आवृत्तिमूलक प्रकृति।

(3) उपनियम (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश में अधिनियम के उपबंध, जिनकी बाबत व्यक्ति हुआ है, विनिर्दिष्ट होंगे और उसमें ऐसे विनिश्चयों के लिए संक्षिप्त कारण अंतर्निहित होंगे।

(4) प्रत्येक ऐसा आदेश न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा तारीख डालकर हस्ताक्षरित होगा।

6. आदेश की प्रति—न्यायनिर्णायक अधिकारी, उसके द्वारा नियमों के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति संबद्ध व्यक्ति को और बोर्ड को भेजेगा।

7. सूचनाओं और आदेशों की तामील—इन नियमों के अधीन जारी की गई किसी सूचना या किए गए किसी आदेश की निम्नलिखित रीति से व्यक्ति को तामील की जाएगी, अर्थात् :—

(क) उसे उस व्यक्ति या उसके मध्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी को परिदत्त या निविदत्त करके;

(ख) उसे उस व्यक्ति को उसके निवास स्थान या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान के, जहां उसने कारोबार किया था या अंतिम बार कारोबार किया था या अभिलाभ के लिए वह स्वयं काम करता है या उसने अंतिम बार काम किया था, पते पर रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजकर; या

(ग) यदि उसे खंड (क) या खंड (ख) के अधीन तामील नहीं किया जा सकता है, तो उसे उस परिसर के, जिसमें वह व्यक्ति निवास करना है या उसका अंतिम बार निवास करना या कारबार करना या अभिलाष के लिए स्वयं काम करना या अंतिम बार काम करना ज्ञात है, बाहरी द्वार या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगाकर और उसकी लिखित रिपोर्ट दो व्यक्तियों द्वारा साक्षित होनी चाहिए।

[फा. सं. 5/3/सी.एम./95]

पी. जे. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 1995

G.S.R. 541(E).—In exercise of the powers conferred by clause (da) of sub-section (2) of Section 29 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) the Central Government hereby makes the following rules for holding inquiry for the purpose of imposing penalty under Chapter VI-A of the said Act, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Securities and Exchange Board of India (Procedure for holding inquiry and imposing penalties by adjudicating officer) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) :

(b) "adjudicating officer" means the officer appointed by the Board as adjudicating officer under Section 15L of the Act :

(c) "inquiry" means the inquiry referred in Section 15-I.

3. Appointment of adjudicating officer for holding inquiry.—Whenever the Board is of the opinion that there are grounds for adjudging under any of the provisions in Chapter VIA of the Act, it may appoint any of its officer not below the rank of Division Chief to be an adjudicating officer for holding an inquiry for the said purpose.

4. Holding of Inquiry.—(1) In holding an inquiry for the purpose of adjudging under sections 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, 15F and 15H whether any person has committed contraventions as specified in any of the section 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, 15G and 15H, the adjudicating officer shall in the first instance, issue a notice to such person requiring him to show cause within such period as may be specified in the notice (being not less than fourteen days from the date of service thereof) why an inquiry should not be held against him.

(2) Every notice under sub-rule (1) to any such person shall indicate the nature of offence alleged to have been committed by him.

(3) If after considering the cause, if any, shown by such person to adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice fixing a date for the appearance of that person either personally or through his lawyer or other authorised representative.

(4) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his lawyer or authorised representative, the offence, alleged to have been committed

by such person indicating the provisions of the Act, rules or regulations in respect of which contravention is alleged to have taken place.

(5) The adjudicating officer shall then give an opportunity to such person to produce such documents or evidence as he may consider relevant to the inquiry and if necessary the hearing may be adjourned to a future date and in taking such evidence the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Evidence Act, 1972 (11 of 1972):

Provided that the notice referred to in sub-rule (3), and the personal hearing referred to in sub-rules (3), (4) and (5) may, at the request of the person concerned, be waived.

(6) While holding an inquiry under this rule the adjudicating officer shall have the power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the acts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.

(7) If any person fails, neglects or refuses to appear required by sub-rule (3) before the adjudicating officer, the adjudicating officer proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.

5. Order of the adjudicating officer.—(1) If, upon consideration of the evidence produced before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied that the person has become liable to penalty under any of the sections specified in sub-section (1) of section 15-I, he may, by order in writing impose such penalty as he thinks fit in accordance with the provisions of the relevant section or sections specified in section 15-I.

(2) While adjudging the quantum of penalty under Section 15-I, the adjudicating officer shall have due regard to the following factors namely :—

(a) the amount of disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the default ;

(b) the amount of loss caused to an investor or group of investors as a result of the default;

(c) the repetitive nature of the default.

(3) Every order made under sub-rule (1) shall specify the provisions of the Act in respect of which default has taken place and shall contain brief reasons for such decisions.

(4) Every such order shall be dated and signed by the adjudicating officer.

6. Copy of the Order.—The adjudicating officer shall send a copy of every order made under rules by it to the person concerned and to the Board.

7. Service of notices and orders.—A notice or an order issued under these rules shall be served on the person in the following manner, that is to say,—

(a) by delivering or tendering it to that person or his duly authorised agent ;

(b) by sending it to the person by registered post with acknowledgement due to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on, or last carried on, business or personally works, or last worked, for gain; or

(c) if it cannot be served under clause (a) or clause (b), by affixing it on the outer door of some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided, or carried on business or personally works or last worked for gain and that written report thereof should be witnessed by two persons.

[F. No. 5/3/CM/95]

P. J. NAYAK, Jt. Secy.

